भारतीय रिज़र्व बैंक में अंक संकलन *

दीपक मोहंती

गवर्नर डॉ.सुब्बाराव, प्रो.आर.राधाकृष्ण, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, डॉ.ऑरेल शूबर्ट. महानिदेशक सांख्यिकी विभाग, युरोपियन सेंट्रल बैंक (इसीबी), उप गवर्नर डॉ.सुबीर गोकर्ण; अन्य प्रतिष्ठित वक्ता प्रो.जे.आर.वर्मा, आइआइएम, अहमदाबाद; प्रो.प्रबाल चौधरी, आइएसआइ, कोलकाता और प्रो. अमित बुबना, आइएसबी, हैदराबाद; उप गवर्नरगण, सहकर्मी कार्यपालक निदेशकगण, वित्तीय एवं शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठित अतिथि, समाचारपत्रों के प्रतिनिधि, श्री ए.बी.चक्रवर्ती, प्रभारी अधिकारी, डीएसआइएम और मित्रो, मैं इस सांख्यिकी दिवस सम्मेलन में आपका स्वागत करता हूँ।

29 जून को सांख्यिकी दिवस सांख्यिकी और भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली में प्रो.प्रशांत चंद्र महालनवीस के बहुमूल्य योगदान का स्मरण करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक भी एक वार्षिक सांख्यिकी सम्मेलन का आयोजन करता है, जो हमारे सांख्यिकीविदों को शिक्षा क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा परिचालन विभागों के साथ परस्पर संवाद के लिए मंच उपलब्ध कराता है। ये दो वार्षिक घटनाएँ हमें रिज़र्व बैंक में सांख्यिकीय कार्य की प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करती हैं और आगे के कार्य के लिए एजेंडा तैयार करने में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। मुझे विश्वास है कि, आज के सम्मेलन की विषय-वस्तु, आँकड़ा अंतराल और केंद्रीय बैंकिंग, इस प्रक्रिया को प्रबलित करेगी।

साक्ष्य आधारित सार्वजनिक नीति और निर्णयन तंत्र में सांख्यिकी एक महत्त्वपूर्ण साधन होती है। इसके साथ-साथ, सांख्यिकी लोकहित का कार्य होता है। वर्षों से, सरकार, रिज़र्व बैंक और व्यावसायिक निकायों यथा, इंडियन एसोसिएशन फॉर रिसर्च इन नैशनल इनकम एंड वेल्थ और इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी द्वारा उपक्रमण किये गये हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आँकड़ा अंतराल की पहचान की जाये। *राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की रिपोर्ट* (2001) ने भारत में आर्थिक डाटाबेस में बड़े अंतरालों की पहचान करने में मदद की है।

वर्ष 2010 में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग ने आधिकारिक सांख्यिकी में सुधार संबंधी अनेक मुद्दों की जाँच-पड़ताल करने के लिए अनेक व्यावसायिक समितियों का गठन किया था। सर्वेक्षणों के संबंध में रिज़र्व बैंक के कार्यदल की रिपोर्ट (2009) में भी महत्त्वपूर्ण आँकड़ा-अंतरालों को आलोकित किया गया है। डाटाबेस में सुधार करने की प्रक्रिया सतत चालू रहने वाली होती है। जबकि आँकड़ा-अंतरालों को पाटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनेक उपक्रमण किये गये है, मैं अपना ध्यान रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये हाल के उपक्रमणों पर केंद्रित रखूँगा।

रिज़र्व बैंक का नीति-फलक बड़ा है और यह एक परंपरागत केंद्रीय बैंक के स्थापित नियमों के परे तक जाता है। हमारा प्राथमिक उत्तरदायित्व है बैंकिंग और वित्तीय सांख्यिकी तथा भुगतान संतुलन सांख्यिकी का संकलन करना। हम कारपोरेट वित्त सांख्यिकी का भी संकलन करते रहे हैं। हम सांख्यिकी की व्याप्ति, गुणवत्ता, आवृत्ति और प्रसार की दृष्टि से निरंतर सुधार किये जाने की आवश्यकता के प्रति सजग रहे हैं। हम विविध अंतरराष्ट्रीय मानकों, यथा, आईएमएफ के एसडीडीएस और बीआईएस डाटाबैंक कार्यक्रम में भाग लेते हैं और सामान्यतः उनके अनुरूप कार्य करते हैं। हम जी-20 डाटा इनिशिएटिव का एक हिस्सा बने रहे हैं, जिसने आँकड़ा संग्रहण के लिए अनेक नये क्षेत्रों की पहचान की है। अब मैं कुछ हाल के उपक्रमणों पर चर्चा करूँगा।

पहला, हमारी बैंकिंग सांख्यिकी की व्याप्ति मानक मौद्रिक एवं विनियामक सीमाओं से बाहर जा कर उसमें समाजार्थिक आयामों को शामिल करती है। हम वाणिज्यिक बैंकों के विशाल शाखा नेटवर्क का डाटाबेस बनाये रखते हैं। हमने हाल ही में अपने वेबसाइट पर *बैंक ब्रांच लोकेटर* की सुविधा प्रदान की है, जो बैंक शाखाओं की विविध विशेषताओं, यथा, अवस्थिति और आबादी समूह, के संबंध में जानकारी देने का एक गत्यात्मक साधन है।

दूसरा, आँकड़ा प्रसार के हमारे हाल के प्रयासों में शामिल हैं: एक उपयोगकर्ता अनुकूल डाटा वेयरहाउस इंटरफेस आरंभ करना, जिसमें डैशबोर्ड्स और कालमानश्रेणी निरूपित रिपोर्टें हों; अनेक नियमित सांख्यिकीय प्रकाशन निकालना, जो सीधे डाटा वेयरहाउस से लिये गये हों, और उन्हें लगभग तत्काल आधार पर अद्यतन करना; आरंभिक बिन्दु के रूप में वेब प्रकाशन के माध्यम से सूचना का प्रसार करना और उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था पर डाटाबेस (डीबीआइई) के संबंध में जारी किये गये आँकड़ों के तुल्यकालिक बनाना; और सीधे डाटा वेयरहाउस के साथ एक्सबीआरएल आँकड़ा संग्रहण के साथ

* 17 जुलाई 2012 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई में 6ठे सांख्यिकी दिवस सम्मेलन के अवसर पर श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक, आरबीआई का स्वागत-भाषण।

एकीकरण में प्रगति करना, ताकि अंततः सभी स्टैंडअलोन आँकड़ा संकलन प्रणालियों को प्रतिस्थापित किया जा सके।

तीसरा, बाह्य खाता सांख्यिकी के संबंध में हाल की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रही है आईएमएफ के समन्वित प्रत्यक्ष निवेश सर्वेक्षण (सीडीआईएस) में हमारा योगदान। यह वृहद डाटाबेस देशवार आवक-जावक प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में जानकारी देता है। भुगतान संतुलन (बीओपी) सांख्यिकी के संबंध में हमने आईएमएफ मैनुअल के छठे संस्करण का कार्यन्वयन अनेक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से पहले किया है।

चौथा, रिज़र्व बैंक औद्योगिक दृष्टिकोण, उपभोक्ता विश्वास और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के क्षेत्र में अनेक तिमाही प्रगामी नमूना सर्वेक्षण करता है, ताकि मौद्रिक नीति-निर्माण में मदद मिल सके। इन सर्वेक्षणों के परिणाम अब एक साथ हमारी समष्टिआर्थिक एवं मौद्रिक गतिविधियों के संबंध में तिमाही रिपोर्ट के साथ, जो मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी की जाती है, पब्लिक डोमेन में प्रसारित किये जाते हैं।

पाँचवाँ, हमने आवास निबंधन प्राधिकरण से प्राप्त लेन-देन कीमतों पर आधारित अपने आवास कीमत सूचकांक (एचपीआई) की व्याप्ति को सात शहरों से विस्तारित कर 9 शहरों तक कर दिया है। इस वर्ष इसमें चार और शहरों के जुड़ने की उम्मीद है। इसके समानांतर हम एक आस्ति-कीमत निगरानी प्रणाली (एपीएमएस) को विकसित कर रहे हैं, जो बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के पास उपलब्ध आवास वित्त आँकड़ों पर आधारित आवास कीमतों में उतार-चढ़ाव का पता लगायेगी।

अंत में, बढ़ती विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं को देखते हुए, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) को पुनर्गठित कर उसे अनुसंधान पर अधिक जोर देने को कहा गया है। एक सुनियोजित अनुसंधान एजेंडा विकसित किया गया, ताकि संस्थागत अपेक्षाओं के अलग-अलग सक्षमताओं के साथ संरेखित किया जा सके। वर्ष 2011 में 23 शोध-प्रबंध विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित किये गये और अन्य सात प्रबंध आरबीआई के वर्किंग पेपर सिरीज में प्रकाशित किये गये।

ये उपलब्धियाँ महत्त्वपूर्ण हैं, परंतु मैं उन व्यापक क्षेत्रों को आलोकित करना चाहता हूँ, जहाँ हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि रिज़र्व बैंक में सांख्यिकी तैयार करने की प्रक्रिया को और भी परिशुद्ध किया जा सके।

पहला, यह महत्त्वपूर्ण होगा कि हम देश में बैंकिंग आधारिकी के अपने डाटाबेस में और सुधार लायें, ताकि हम वित्तीय समावेशन की सीमा को माप सकें और इस संबंध में किये गये विविध नीतिगत उपायों की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन कर सकें। प्रयास यह होना चाहिए कि सभी विश्लेषणात्मक आँकड़ों को, जिनमें वे आँकड़े शामिल हैं, जिनका संग्रह मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ (बीएसआर) द्वारा किया जाता है, डीबीआइई के माध्यम से हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाये।

दूसरा, यह आवश्यक है कि सांख्यिकीविदों और बैंक पर्यवेक्षकों के बीच निकट समन्वय हो, वाणिज्यिक और सहकारी बैंकिंग, दोनों क्षेत्रों में, ताकि पर्यवेक्षकीय समीक्षा प्रक्रिया में आंकड़ा अंतरालों की पहचान हो और उनका शमन किया जा सके तथा बैंकिंग प्रणाली के लिए युक्तियुक्त जोखिम मूल्यांकन सुविधाजनक हो।

तीसरा, आँकड़ा रिपोर्टिंग प्रणाली को स्रोत प्रणाली से स्वतः आँकड़ों का प्रग्रहण करने की दिशा में सक्रिय किये जाने की आवश्यकता है। यह अनिवार्य होगा कि विश्लेषण के लिए प्रयुक्त आँकड़ों की डाटा फिल्टरों के प्रयोग के माध्यम से संवीक्षा की जाये और उन्हें मान्य बनाया जाये, ताकि आँकड़ों को उसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाये और यह भी कि बड़े डाटा सेटों में अंतर्निहित ऊल-जलूल आँकड़ों की पहचान कर उन्हें हटाया जाये। यह समष्टि वित्तीय आँकड़ों को अधिक प्रयोग लायक बनायेगा। रिज़र्व बैंक के आईटी विजन को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास किया जाना चाहिए कि युक्तियुक्त स्ट्रेटथ्रू प्रोसेसिंग सिस्टम को अपना कर रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं से स्वतः आँकड़ा प्रवाह हो। संसाधन के लिए डाटा वेयरहाउस का तगड़ा उपयोग किया जाना जाहिए, ताकि आँकड़ों की गुणवत्ता, अखंडता और सुपुर्दगी में सुधार हो।

चौथा, 'मुद्रास्फीति प्रत्याशा' हमारे मौद्रिक विश्लेषण में केंद्रीय स्थान पर आ गया है। इस संबंध में परिवारों के लिए तिमाही प्रगामी मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रिया के लिए महत्त्वपूर्ण निविष्टि प्रदान करता है। लेकिन यह शहर-केंद्रित होता है, क्योंकि इसकी व्याप्ति इस समय 12 शहरों तक सीमित है। अतः यह आवश्यक है कि इस व्याप्ति को और अधिक व्यापक आधार वाला बनाया जाये, ताकि हमारी प्रणाली में प्रत्याशाओं की विषमता को बेहतर तरीके से समाहित किया जा सके।

अंत में, प्रमुख समष्टिआर्थिक वैरिएबलों का पूर्वानुमान लगाना वैश्विक वित्तीय संकट के बाद कठिन हो गया है, क्योंकि एक ओर वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था के बीच और दूसरी ओर वित्तीय एवं संपदा क्षेत्र के बीच आपसी प्रतिसूचना अधिक जटिल हो गई है। इस संदर्भ में, समष्टि-नीतियों का उचित प्रभाव मूल्यांकन करना कठिन हो गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बैंकों के पास मौजूद मानक मॉडलों की वृद्धि और मुद्रास्फीति के बारे में भविष्यकथन करने की सक्षमता पर

सवाल उठाये जा रहे हैं। आधारभूत डीएसजीई मॉडलों की प्राथमिक धारणाएँ नीति-निर्माताओं और शिक्षाविदों, दोनों के आक्रमण झेल रही हैं। अतः, इस बात की आवश्यकता है कि बढ़ी हुई अनिश्चितता, लिवरेज और वैश्विक सहबद्धताओं के आलोक में मॉडलिंग रणनीति का पुनरावलोकन किया जाये। यह महत्त्वपूर्ण है कि आर्थिक-वित्तीय ढाँचे के अंतर्निहित जटिल संबंधों का पता लगाने के लिए युक्तियुक्त सांख्यिकीय साधनों का उपयोग किया जाये।

देवियो और सज्जनो, हम भाग्यवान हैं कि हमारे बीच ऐसे प्रकांड विद्वान उपस्थित हैं, जो न केवल निष्णात सांख्यिकीविद हैं, बल्कि इनमें से कुछ तो सांख्यिकीय प्रशासन के शिखर पर स्थित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का विचार-विमर्श न केवल रिज़र्व बैंक में हमारे सांख्यिकीय एजेंडे को निश्चित करने में मार्गदर्शन करेगा, बल्कि भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली को बहुत हद तक सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा, जिसके लिए प्रो.महालनवीस ने अथक परिश्रम किया था।

मैं एक बार फिर से हमारे सभी वक्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आगे आने वाले बौद्धिक सत्र की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ।